12 00 hrs.

RE. STATEMENT BY PRIME MINISTER

MR SPEAKER : After the Calling Attention Notice and the papers are laid the Prime Minister will make a statement on the border situation.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DIFFICULTIES FACED BY SUGAR FACTORIES AND CANE GROWERS IN UP AND OTHER STATES

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Gorakhpur) : Sir, I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

> "The reported difficulties faced by sugar factories and cane growers in UP and other States owing to sugarcane price having been fixed by the government at a lower level than the recovery price."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) : The Government of India fix only the minimum price of sugarcane payable by vacuum pan sugar factories. The actual price to be paid is settlled between the sugarcane growers as sellers and sugar factories as buyers. The minimum sugarcane price is determined after taking into account the recommendations received from the Governments of the sugar producing States, Associations of Sugarcane growers and Sugar Industry, Agricultural Prices Commission, etc. In fixing this price various factors such as the cost of production of sugarcane, the return to the grower from alternative crops and the general trend of prices of agricultural commodities, the availability of sugar to the consumer at a fair price and the price at which suugar produced from sugarcane is sold by producers of sugar, are also taken into account.

For sugarcane purchased by vacuum pan sugar factories during the 1971-1972 season, the Government after careful consideration of all aspects have decided to continue the basic minimum sugarcane price at Rs. 7.37 per quintal linked to a recovery of 9.4 percent or less with a premium of 6.6 paise per quintal for every increase of 0.1 percent in recovery above 9.4 percent. Government did not consider it necessary to increase the minimum price of sugarcane as this would have pushed up the sugar prices further. Increase in the statutory minimum price would have also repercussions on the prices of other competing crops thereby aggravating the inflationery trends.

The minimum price fixed is expected to be only a national price as it has been made clear to the sugar industry that they are expected to pay a higher price for sugarcane than the minimum fixed by the Government, in view of the higher realisations they are getting at the present level of sugar prices. As per information received form the industry it is understood that they propose to pay sugarcane as under:—

		Rs. per quintal
West U.P.		8.50
Central U.P.		8.00
East U.P.		8.00
Punjab		9.00
Haryana	up to	8.50
Maharashtra		11.50 ex field.
Mysore		9.50 to 11.50
Andhra Pradesh		9.00
Tamil Nadu		7 50 to 8.00

श्री नरसिंह नारायण पांडे : श्रीमन्, आप को याद होगा कि पिछले सत्र मे भी केन प्राइस के एरियर्स, शुगर केन प्राइस और सरकार की आल इंडिया की क्या शुगर नीति हो, इसके सम्बन्ध मे विशुद्ध रूप से व्याख्या की गई थी और उस समय भी प्रोफेसर शेर सिंह साहब ने कहा था कि जिस समय केन प्राइस तय की जायगी, केन प्राइस को तय करने के लिए जो कुछ भी आज स्ट्रक्चर है, आज की महंगाई है, फर्टिलाइजर का दाम ज्यादा हो गया, तमाम चीज जिन से शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उसका दाम ज्यादा हो गया, यह सब कंसिडर किया जायगा और उसके बाद किसानों को हर प्रकार से संतुष्ट किया जायगा क्योंकि करोड़ों लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि उसी तरीके से शुगर पालिसी तय की जाय और केन प्राइस फिक्स की जाय। श्रीमन्, आज मुझे यह वक्तव्य देख कर

बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस इसलिये हुआ कि मन्त्री महोदय ने एक टेक्निकल वक्तव्य दे दिया और अगर आप इस बयान को देखेंगे तो 1970-71 में यही बयान दिया गया और आज उसको बनाकर के 71-72 कर दिया गया है। यह इस बयान की सूची है। हमारी सरकार किस तरह से केन ग्रोअर्स के बारे में कितनी कंसिडरेट है, यह इसको देखकर आपको पता चल जायगा।

इसमें तीन बातें उठाई गई है। पहली बात रिकवरी की मंत्री महोदय ने उठाई कि केन ग्रोअर्स एसोशिएशन ने और सेलर्स ने तथा शुगर फैक्ट्री ओनर्स ने सबने मिलकर यह तय किया कि 7 रुपये 37 नये पैसे गन्ने का दाम तय किया जाय। मैं जानना चाहता हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि शुगर मिल एसोशिएशन ने जो मालिकों का एसोशिएशन हैं, उन्होंने स्वयं आपको कहा कि गन्ने की ईल्ड आज 30 से 35 परसेंट कम हो गई है और कम होने के बाद आज बहुत सा गन्ना खांडसारी और गुड़ में जा रहा है। साथ ही हिन्दुस्तान की अलग अलग स्टेट्स में अपने अपने तरीके के नियम बने हुए है जिससे हमें 30 परसेंट गन्ना भी मुश्किल से मिलने की आशा है। ऐसी स्थिति में जब तीस परसेंट भी गन्ना नहीं मिलेगा और 120 दिन का आपका ड्यूरेशन है, तो क्या सरकार ने इस बात का ख्याल किया ?

उन्होंने स्वयं कहा कि रिकवरी के हिसाब से इसकी कीमत तय की जाए। रिकवरी नौ प्वाइंट से ज्यादा है। बहुत से मुख्य मंत्रियो ने जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी हैं, बार बार यह कहा है कि गन्ने का दाम कम से कम दस रुपये होना चाहिये। सात रुपये 37 पैसे में कोई गन्ना देने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री जी ने बहुत ही उदारतापूर्वक कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे लेकिन आज मुझे उनका वक्तव्य देख कर बड़ी निराशा हुई है। उन्होंने कंट्रेडिक्ट्री स्टेटमेंट दिया, अगर मैं यह कहूं तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ तो कहते हैं कि 7 रुपये 37 पैसे प्राइस फिक्स करते हैं और दूसरी ओर मिल मालिकों से फिगर लेकर कोट कर देते हैं कि हर फैक्ट्री 7 रुपये 37 पैसे से ज्यादा दाम दे रही है। मन्त्री जी को मालूम है कि केन रिजर्वेशन का एक जोन होता है। उस केन रिजर्वेशन के जोन के दस दस बारह बारह मील की एरिया के सारे किसानों को फोर्स किया जाता है प्रान्तीय सरकारों के कानूनों के मुताबिक कि वे अपना गन्ना अमुक मिल को ही दे सकते है, उससे बाहर नही दे सकते, न गुड़ बना सकते है और न खांडसारी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसान बिल्कुल विवश हो गया है कि 7 रुपये 37 पैसे में उसका गन्ना जबर्दस्ती उससे ले लिया जाए। पिछले साल की फिगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आज भी केन एरियाज के एरियर का रुपया बकाया है और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए खाद्य मन्त्री ने 1968 से लेकर 1971 तक, इन तीन सालों में कोई चीनी नीति नहीं बनाई। आप कहते हैं कि प्राइस स्टेबल हो जाएगी। मैं आपको कोटेशन के द्वारा बताना चाहता हूं कि मई में जब आपने डिकंट्रोल किया तो प्राइस को फिक्स आप क्यों नहीं कह पाए ? अगर आप समझते थे कि डिकंट्रोल करने से प्राइस ठीक मिल जाएगी तो मैं आपके सामने कुछ हफ्तेवार आंकड़े रखना चाहता हूं, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, केवल इन दो जगहों के।

हापुड़ से पहली मई को जब आपने चीनी का डिकंट्रोल किया तो उस समय 178 रुपये क्विंटल का भाव था और मुजफ्फरनगर में 193 रुपये का भाव था। 8 मई 1971 को यह भाव हापुड़ में 196.67 रु० और मुजफ्फरनगर मे 196.25 रुपये हो गया। 22 मई को यह दाम घटा। हापुड़ में 181 रुपये हुआ और मुजफ्फरनगर से 195 रुपये। 29 मई को हापुड़ में 183 रुपये 50 पैसे और मुजफ्फरनगर मे 187 रुपये। 5 जून को 177 रुपये और 187 रुपये। 12 जून को 176 रुपये और 186 रुपये। 3 जुलाई को 175 रुपये और 184 रुपये। 24 जुलाई को

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

168 रुपये और 179 रुपये । 14 अगस्त को 171.1 और 185 रुपये । 4 सितम्बर को 192 रुपये और 196 रुपये । इस प्रकार से यह भाव क्रमशः हापुड और मुजफ्फरनगर में रहे । 30 अक्तूबर को आप देखेंगे कि हापुड में 183 रु० भाव हो गया और मुजफ्फरनगर मे 192 रु० हो गया । 6 नवम्बर को हापुड मे 186 रु० और मुजफ्फरनगर मे 196 रुपये हो गया ।

अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि 200 रु० से 205 रु० प्रति क्विटल के हिसाब से चीनी बिक रही है और दिल्ली के बाजारो से 2 रु० 15 पैसे से लेकर 2 रु० 20 पैसे किलो के हिसाब से बिक रही है । मै जानना चाहता हू कि आपकी यह कौनसी शुगर नीति है ?

आपने 1962 मे कहा था—मैं टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट का उद्धरण आपके सामने रखना चाहता हू—

> "In 1962 the Government adopted a system of minimum price fixation related to the recovery of sugar from sugarcane "

आपने यह पालिसी 1962 मे निर्धारित की थी, आज मिल ओनर्स एसोशियेशन जो रिप्रेजेन्टेशन आपको देता है, उसमे कहता है कि आप गन्ने की कीमत 9 रुपये से कम मत कीजिये, तब आपको गन्ने की मिनिमम प्राइस फिक्स करने में कौनसी दिक्कत है । आपको किस एम्पलायर एसोशियेशन ने कहा कि 7 रु० 37 पैसे तय करे । आप केन-ग्रोअर्स एसोसियेशन की बात करते है—किस केन ग्रोअर्स एसोसियेशन ने आपको ऐसा रिप्रेजेन्टेशन दिया, जिसके तहत आपने कहा कि केन ग्रोअर्स एसोशियेशन से राय ले ली है । मैं पूछना चाहता हूं कि किस लेबर और कन्ज्यूमर से आपने राय ली है ?

आज स्थिति यह है कि 1968 से लेकर आज तक, यह 1971-72 का साल है, इन तीन सालों मे इस खाद्य मंत्रालय के ब्यूरोक्रैट्स ने सारी गवर्नमेंट को बदनाम किया है, हमारी पालिसीज को बदनाम किया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज तक हमारी कोई निश्चित शुगर पालिसी नही बन पाई । हमारे किसानो को रिजर्व जोन के नाम पर कहा जाता है कि 7 रु० 37 पैसे गन्ने का भाव है ।

अध्यक्ष महोदय : मै आपके प्रश्न का इंतजार कर रहा हू ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे मैं सब फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हू और उसी के आधार पर सवाल कर रहा हू ।

जब मैंने यहा पर यह कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल गन्ने की फसल 30 से 35 प्रतिशत कम हो गई है, इस बात को हम सब लोगो ने जो यहा पर बैठे हुए है, सब ने स्वीकार किया है । पिछले सत्र मे जब इस बात पर चर्चा हुई थी, उस समय मन्त्री महोदय ने जो कहा था, अगर मै उसको यहा पर उद्धृत करू तो सदन का बहुत समय चला जायगा । सारे सदस्य उसको जानते है । इन्होने उस वक्त कहा था, हम सारी चीजो को अपने वियु मे लेकर शुगर केन की प्राइस तय करेंगे, लेकिन हुआ यह कि जो बयान इन्होंने 1970-71 मे दिया था, उसी को 1971-72 मे लाकर सदन में पढ़ दिया—यह आपका खाद्य मन्त्रालय है ।

मैं आपकी कमजोरियो को समझता हूं, अगर कोई फैसला होता है तो चाहते हुए भी आप उसको लागू नहीं कर सकते हैं । मुझे खेद है कि खाद्य मन्त्री जी इस समय यहां मौजूद नहीं है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बम्बई कांग्रेस में इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि शुगर इण्डस्ट्री को नेशनलाइज किया जाय । जब तक शुगर इण्डस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन नहीं होगा, कन्ज्यूमर को सस्ते दामों पर चीनी नहीं मिल पायेगी, मजदूरों को मजदूरी नहीं

मिल पायेगी, किसानों को गन्ने के सही दाम नहीं मिल पायेंगे। लेकिन मुझे दुख है कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर आपके रास्ते में कोई कानूनी रुकावट है तो इस समय इस सदन में आप का बहुमत है, आपको हक है कि आप उस कानून को संशोधित करें और सही तरीके से उस पर अमल करें।

आपने एसेंशल कमाडिटीज एक्ट में शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर निकाला, उसमें आपने यह तय किया कि गन्ने का भाव क्या होगा, उसके लिये आपने मोटी-मोटी पांच बातें तय कीं, मैं आपकी इजाजत से उनको पढ़ देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिये।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मै यह सवाल ही कर रहा हूं, जिसका जवाब मन्त्री जी को देना है। आपका यह आर्डर 16 जुलाई, 1966 का है, जिसको मिनिस्ट्री आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर ने निकाला है। इस आर्डर की धारा 3 मे लिखा है—

The Central Government may, after consultation with such authorities, bodies or associations as it may deem fit, by notification in the official Gazette, from time to time, fix the minimum price of sugarcane to be paid by producers of sugar or their agents for the sugarcane purchased by them, having regard to the cost of production of sugarcane; the return to the grower from alternative crops and the general trend of prices of agricultural commodities.

श्रीमन्, मैं आपके आर्डर की तरफ ध्यान दिलाते हुए आपसे जानना चाहता हूं कि आपने शुगर-केन के दामों को तय करने के लिए किन नीतियों का सहारा किया, जिसके अन्तर्गत आप कहते हैं कि 7 रु० 37 पैसे कम से कम दाम होना चाहिये ? गन्ने की बुआई अगले सीजन में कम होने जा रही है, हिन्दुस्तान की सारी शुगर इण्डस्ट्री बरबाद होने जा रही है। आज गन्ना की फसल 70 परसेंट रह गई है। अगर आपकी यही नीति जारी रही तो सारे हिन्दुस्तान में शुगर स्केअरसिटी पैदा हो जायगी, जिसकी चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं।

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य ने कई बातें रखी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें मुजफ्फरनगर और हापुड की कुछ फीगर्स दीं। उनको शायद याद नहीं रहा कि हमने डी-कन्ट्रोल 25 मई को किया था, 2 मई को नही किया था। 2 मई से 25 मई तक की उन्होंने जो फिगर्स दी है, उनमें शुगर की कीमत बढ़ रही थी, लेकिन 25 मई के बाद जब हमने शुगर को डी-कन्ट्रोल किया तो कीमतें गिरनी शुरू हो गई थी ...

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : दुनिया में डी-कन्ट्रोल से प्राइसेज कहा गिरती है, यह कहां की इकानामिक्स है ?

प्रो० शेर सिंह : अब कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ रही है, यह ठीक है, इसीलिये हमने मिल ओनर्स से कहा कि आपको शुगर की ज्यादा कीमतें मिल रही है, इसलिये फ्लोर प्राइस कुछ भी हो, आपको कीमतें उसी हिसाब से देनी चाहिए। मैंने अपने वक्तव्य मे ये सूचनायें आपको दी है कि किन किन स्टेट्स मे कितना-कितना पैसा गन्ने का मिलना है और वह सब जगह 7 रु० 37 पैसे से ज्यादा हैं।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : प्राइस आपको फिक्स करनी है, लेकिन आप करते नही हैं, मिल-ओनर्स को कहते है कि इतना दो। आपके हाथ मे अधिकार है, लेकिन आप खुद नही करना चाहते हैं।

प्रो० शेर सिंह : सरकार कम से कम कीमत मुकर्रिर करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कम ही दिया जाय, ज्यादा दिया जा सकता है। सैलर और बायर के हिसाब से खरीदने और बेचने वाले आपस में बातचीत करके फैसला कर सकते हैं और ऐसा हो रहा है।

[प्रो० शेर सिंह]

माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में और भी बहुत सी बातें कही हैं—शुगर-केन प्राइस फिक्स करते समय हम को कुछ बातें याद रखनी चाहिये। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही वे सब चीजें बतला दी हैं और जितने फैक्टर्ज हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाया है।

एक आपत्ति आप ने 1970-71 की उठाई है, उसके लिये मुझे खेद है, इस स्टेटमेंट मे एक टाइप की गलती हो गई है, मैंने तो पढ़ते समय उसको ठीक कर लिया था, लेकिन जो कापी आप के पास गई है, उसमें 1970-71 छप गया है, जबकि यह 1971-72 है। इसका यह अर्थ नही है कि यह 1970-71 में तैयार हुआ है, यह गलती से टाइप हो गया है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास जो कापी आई है, उसमें दुरुस्त है। मेम्बर्ज को दुरुस्त कर के देना चाहिये था।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर): मन्त्री महोदय सदन में क्या स्टेटमेंट दे रहे है, जो एक साल पहले तैयार हुआ था, वह दे रहे है या इस साल का दे रहे है। यह आज का स्टेटमेट है। 70-71 में यह प्राइसेज नही थी।...

श्री नरसिंह नारायण पांडे: यू० पी० के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि गन्ने का दाम दस रुपए दिया जाये।

प्रो० शेर सिंह: विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग सुझाव आये है। मै उनको बता दूं:

Andhra Pradesh	Rs. 7.37 (linked to 9.5 per cent recovery)
Bihar	Rs.10
Gujarat	(No suggestion has been received)
Haryana	Rs. 10
Kerala	Rs. 7.37
Madhya Pradesh	Rs. 8 (linked to 9.4 per cent recovery)
Mysore	Rs. 7.67
Rajasthan	Rs. 7.37
Tamil Nadu	Rs. 7.37 (if the recovery is less, the price would also be less)
U.P.	Rs. 10 (linked to 9 per cent recovery)

Bihar Sugarcane Growers' Association: Rs. 10.00

Indian Sugar Mills Association: Rs. 9

Deccan Sugar factories Association Rs. 8

South Indian Sugar Mills Association : Rs. 7.37

National Federation of Co-operative Sugar Factories Ltd. Rs. 7.37 (linked to recovery of 8.4 per cent)

ये अलग-अलग सुझाव हमारे पास आये है।

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj): I have heard the hon. Minister with great attention and he has said that he hopes that the factories will pay a higher price for sugarcane. The situation now is exactly. similar to that which prevailed in 1967-1968. At that time, the price of sugarcane was Rs. 15 per quintal. But then there was partial control on sugar; the sugar factories sold 40 per cent in the free market and 60 percent in the controlled market. So, at that time, they were enabled to pay a higher price. But if Government do not immediately resort to partial decontrol and still expect higher price for sugarcane to be paid, then it is impossible. The factories will not then pay higher price. Besides a price of Rs. 8 per quintal will not be sufficient in this season.

The price of sugarcane is determined by the price of gur. As you know, gur is selling at Rs. 125 per quintal in the market. One quintal of gur is made from 8½ quintals of sugarcane, which gives the grower Rs. 15 per quintal for his sugarcane. The growers gets Rs. 15 per quintal for his sugarcane if he converts his sugarcane into gur. Then how can you expect that a grower will sell it to the sugar factory and not make gur? So, unless the price of sugarcane is fixed at Rs. 15 per quintal, the sugar factories will not get sugarcane this year, So, merely saying the price paid by factories will be Rs. 8 or 9 will not do. The Chief Minister of our State has himself suggested a minimum price of Rs. 10. Bihar also has suggested

a similar price. But Government have fixed only Rs. 7.37 per quintal and hope that the factories will get sugarcane at this price. This is impossible.

So, my first suggestion is that partial decontrol of sugar must be announced immediately. I say that the hon. Minister must be realistic. He must not think that merely because the factories have promised, they will pay a higher price. They will not pay, unless they are enabled to sell a portion of the sugar in the free maket at a higher price. So, I suggest that Government should announce immediately partial decontrol of sugar as they did in 1967-68 and make 40 per cent availiable for sale in the free market; and let the factories sell it at a higher price in free market. The factories must then be made to pay canegrowers a price of Rs. 15 per quintal. The remaining 60 per cent can then be sold in the controlled market as Government stock on prices fixed by Government. My second suggestion is that unless the grower is given at least Rs. 15 per quintal for his sugarcane, there will be less sowings of cane in the coming sowing season. If this year the sowings of cane are small, next year the sugarcane crop will be even smaller with the result that sugar may sell at Rs. 5 per kilo.

I therefore think Government must take proper counsel and must not play with this matter. Your experts say that if you raise the price of cane, the prices of other commodities will also go up. Already the price of wheat is high. It is Re. 1. per kilo. So are the prices of other commodities. If you do not raise the price of cane, you may not have enough sugar next year. Therefore, it is necessary to give a higher price to cane. Do you not wish that there should be a reasonable price at which sugar should be available next year. If that is your wish, you must pay a price of at least Rs. 15 per quintal to the canegrower this season. To keep the price of sugar within reasonable limits next year, you must raise the price of cane to Rs. 15 per quintal so that there may be higher production of sugarcane next year as a result of larger sowings. Without that, a reasonable price for sugar next year is impossible.

Unless you have partial decontrol, you will not be able to have more production of sugar this year or next year. Then only there will be more sugar production and there will be a free market also in sugar.

PROF. SHER SINGH: I have already stated in my main statement that millowners are actually paying the prices indicated to the sugarcane growers. From several States we got this information. Several mills have started functioning and they are paying these prices. This is the case in Mysore, Maharashtra, Western UP, Haryana and so on where the mills have started functioning. The prices are higher and the millowners are in a position to pay these prices. Therefore, the fear in the mind of the hon. member that prices are not up to that level which he wants is groundless. The prices have gone up to the level and these prices which are prevailing are actually being paid by the millowners.

As for his suggestion to reintroduce partial decontrol, that will be examined.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): May I draw your attention to the fact that the decision on this question of fixation of price of sugarcane is a decision at the Cabinet level and so only the Prime Minister can indicate whether they have any inention of reviewing or reconsidering the matter. So it is not fair to ask this Minister to explain this. This question has been agitating members for sometime and it is only fair that the Prime Minister should answer it.

MR. SPEAKER : The Minister can answer it.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, प्राइम मिनिस्टर यहां पर हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि दस रुपये से कम पर किसानों का दाम आता नहीं है, उनको बड़ी तकलीफ है, इस बात को वे देखें ।

12.29 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Radiation Protection Rules

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : I beg to lay on the Table a copy of the Radiation